

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

247

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़, देहरादून- 248001

Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फ़ैक्स न० (0135) -2713724 फ़ोन न०(0135) - 2713551

संख्या/816 /xxv-12(P-14)/2021 देहरादून : दिनांक 28 मार्च, 2024

अतिरिक्त शुल्क के लिए सूचना का प्रपत्र

सेवा में,

श्री कनक सिंह लिंगवाल,
ग्राम पो0 -भल्ले गांव
बागवान
जनपद-टिहरी गढवाल।
मो0न०-9870712485

पंजीकृत

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना/अतिरिक्त शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 18.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा मांगी गयी सूचना सामग्री को एकत्रित करने और इच्छित रूप में उपलब्ध करने पर सरकार द्वारा निम्नलिखित दरों के आधार पर रू0 222.00(रू0 दो सौ बाइस) अतिरिक्त शुल्क देय होता है तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना 05 पृष्ठों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या	सामग्री या व्यय की मद	दर	कुल धनराशि
बिन्दु सं०-03	111 पेज	रू0 2.00 प्रति पेज	रू0 222.00

अतः उक्त धनराशि की यथाशीघ्र पोस्टल आर्डर अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के नाम बना हो प्रेषित करें। स्वतः स्फूर्त प्रकटन हेतु सूचनायें मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय की वेबसाइट <https://ceo.uk.gov.in> पर भी उपलब्ध है। मांगी गयी सूचना को उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यवाही उक्त अतिरिक्त शुल्क जमा करने के बाद ही प्रारम्भ होगी। इस पत्र की तिथि से अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने की तिथि तक का समय सूचना उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित 30 दिनों में नहीं गिना जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4-सुभाष रोड़,
देहरादून-248001

भवदीय,

B. S. Lawat

(बसन्त सिंह रावत)

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

मो0न०-9411740189

पू0संख्या- /xxv- 12(P-14) /2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि:-1. लोक सूचना अधिकारी/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून, पौड़ी गढवाल, अल्मोडा, उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार को उक्त अनुरोध पत्र की प्रति इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या-01 से सम्बन्धित सूचना आपके कार्यालयों से सम्बन्धित है, फलस्वरूप उक्त अनुरोध पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) में हस्तान्तरित किया जा रहा है कृपया अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

B. S. Lawat

अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

मो0न०-9411740189

दिनांक - 18-03-2024

अनुरोधकर्ता - कानक सिंह सिंगवाल

ग्राम-पो. - भल्लेगाँव

बागवान टि. 570 - 249126

सेवा में,

लोक सू. अधिकारी/मु. निर्वाचन अधिकारी
राज्य-चुनाव आयोग उत्तराखण्ड

विषय- RTI Act-2005 के तहत निम्न बिन्दुओं की सूचना उपलब्ध करने के सम्बन्ध में

बिन्दु सं. 1 - वर्तमान सांसदों के नामांकन पर एवं सम्बन्धित संसदीय क्षेत्र से व्योम-पत्र की प्रति उपलब्ध कराये,

बिन्दु सं. 2 - संसदीय निर्वाचन हेतु निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार-प्रसार करने सम्बन्धित निषेधों का व्योम एवं व्योम की सीमा बताये,

बिन्दु सं. 3 - आदर्श आचार संहिता की प्रति उपलब्ध कराये,

सुलभ सं. 10-200
जे.आ. सं. 60F 134386

अनुरोधकर्ता Kanakk Singh
Kanak Singh
Singwal
9870712485

1
अ. 4. 2

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. ECI/PN/02/2022

Dated: Jan 06, 2022

PRESS NOTE

Limits of candidate's expenses Enhanced

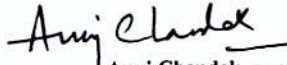
Last major revision in the election expenditure limit for candidates was carried out in 2014, which was further increased by 10% in 2020. Simultaneously, the Election Commission formed a committee comprised of Sri Harish Kumar, retd. IRS Officer, Sri Umesh Sinha, Secretary General and Sri Chandra Bhushan Kumar, Sr. Deputy Election Commissioner in Election Commission of India to study the cost factors and other related issues, and make suitable recommendations. The Committee invited suggestions from political parties, Chief Electoral Officers and Election Observers. Committee found that there has been increase in number of electors and Cost Inflation Index since 2014 substantially. It also factored into the changing modes of campaigning, which is gradually shifting to virtual campaign.

Having regard to demand from political parties to raise existing election expenditure limit for candidates and increase in electors from 2014 to 2021 from 834 million to 936 million (up by 12.23 %) and rise in Cost Inflation Index from 2014-15 to 2021-22 from 240 to 317 (up by 32.08%), the Committee furnished its recommendations to enhance the ceiling limit. The Commission has accepted the recommendations of the Committee and has decided to enhance the existing election expenditure limit for candidates. Accordingly, revised limits have now been notified by M/O Law, Justice and Legislative Department, which are as under:

For Parliamentary Constituencies (PCs)	
Earlier expenditure limit (2014)	Enhanced expenditure limit now
Rs. 70 Lakh	Rs. 95 Lakh
Rs. 54 Lakh	Rs. 75 Lakh

For Assembly Constituencies (ACs)	
Earlier expenditure limit (2014)	Enhanced expenditure limit now
Rs. 28 Lakh	Rs. 40 Lakh
Rs. 20 Lakh	Rs. 28 Lakh

These limits will be applicable in all upcoming elections.


Anuj Chandak . . .
Joint Director (Media)

2

रजिस्ट्री सं. बी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232461
CG-DL-E-06012022-232461

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2022/पौष 16, 1943
No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2022/PAUSHA 16, 1943

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2022

का.आ. 72(अ)—केंद्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 में, विद्यमान सारणी और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् :-

*सारणी

क्रम संख्या	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	निम्न में से किसी एक में निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	सभा निर्वाचन-क्षेत्र
1	2	3	4
		रुपए	रुपए
	I. राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	95,00,000	40,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	75,00,000	28,00,000
3.	असम	95,00,000	40,00,000

116 GI/2022

(1)

3

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

4.	बिहार	95,00,000	40,00,000
5.	छत्तीसगढ़	95,00,000	40,00,000
6.	गोवा	75,00,000	28,00,000
7.	गुजरात	95,00,000	40,00,000
8.	हरियाणा	95,00,000	40,00,000
9.	हिमाचल प्रदेश	95,00,000	40,00,000
10.	झारखंड	95,00,000	40,00,000
11.	कर्नाटक	95,00,000	40,00,000
12.	केरल	95,00,000	40,00,000
13.	मध्य प्रदेश	95,00,000	40,00,000
14.	महाराष्ट्र	95,00,000	40,00,000
15.	मणिपुर	95,00,000	28,00,000
16.	मेघालय	95,00,000	28,00,000
17.	मिजोरम	95,00,000	28,00,000
18.	नागालैंड	95,00,000	28,00,000
19.	ओडिशा	95,00,000	40,00,000
20.	पंजाब	95,00,000	40,00,000
21.	राजस्थान	95,00,000	40,00,000
22.	सिक्किम	75,00,000	28,00,000
23.	तमिलनाडु	95,00,000	40,00,000
24.	तेलंगाना	95,00,000	40,00,000
25.	त्रिपुरा	95,00,000	28,00,000
26.	उत्तर प्रदेश	95,00,000	40,00,000
27.	उत्तराखंड	95,00,000	40,00,000
28.	पश्चिमी बंगाल	95,00,000	40,00,000
II. संच राज्य क्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	75,00,000	-
2.	चंडीगढ़	75,00,000	-
3.	दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	75,00,000	-
4.	दिल्ली	95,00,000	40,00,000
5.	लक्ष्यद्वीप	75,00,000	-
6.	पुडुचेरी	75,00,000	28,00,000
7.	जम्मू-कश्मीर	95,00,000	40,00,000
8.	लद्दाख	75,00,000	-

[फा. सं. एच-11019/7/2020-वि. II]

दिवाकर सिंह, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिमूचना संख्यांक का.आ. 859(अ), तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिमूचना संख्यांक का.आ. 3667(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

4

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2022

S.O. 72(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 77 read with section 169 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Central Government, after consulting the Election Commission of India, hereby makes the following rules further to amend the Conduct of Elections Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Conduct of Elections (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Conduct of Elections Rules, 1961, in rule 90, for the existing Table and entries relating thereto, the following Table and the entries shall be substituted, namely:—

"TABLE

S. No.	Name of State or Union territory	Maximum limit of election expense in any one	
		Parliamentary constituency	Assembly constituency
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
I. STATES			
1.	Andhra Pradesh	95,00,000	40,00,000
2.	Arunachal Pradesh	75,00,000	28,00,000
3.	Assam	95,00,000	40,00,000
4.	Bihar	95,00,000	40,00,000
5.	Chhattisgarh	95,00,000	40,00,000
6.	Goa	75,00,000	28,00,000
7.	Gujarat	95,00,000	40,00,000
8.	Haryana	95,00,000	40,00,000
9.	Himachal Pradesh	95,00,000	40,00,000
10.	Jharkhand	95,00,000	40,00,000
11.	Karnataka	95,00,000	40,00,000
12.	Kerala	95,00,000	40,00,000
13.	Madhya Pradesh	95,00,000	40,00,000
14.	Maharashtra	95,00,000	40,00,000
15.	Manipur	95,00,000	28,00,000
16.	Meghalaya	95,00,000	28,00,000
17.	Mizoram	95,00,000	28,00,000
18.	Nagaland	95,00,000	28,00,000
19.	Odisha	95,00,000	40,00,000
20.	Punjab	95,00,000	40,00,000
21.	Rajasthan	95,00,000	40,00,000
22.	Sikkim	75,00,000	28,00,000
23.	Tamil Nadu	95,00,000	40,00,000

(S)

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

24.	Telangana	95,00,000	40,00,000
25.	Tripura	95,00,000	28,00,000
26.	Uttar Pradesh	95,00,000	40,00,000
27.	Uttarakhand	95,00,000	40,00,000
28.	West Bengal	95,00,000	40,00,000
II. UNION TERRITORIES			
1.	Andaman and Nicobar Islands	75,00,000	-
2.	Chandigarh	75,00,000	-
3.	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	75,00,000	-
4.	Delhi	95,00,000	40,00,000
5.	Lakshadweep	75,00,000	-
6.	Puducherry	75,00,000	28,00,000
7.	Jammu and Kashmir	95,00,000	40,00,000
8.	Ladakh	75,00,000	- "

[F. No. H-11019/7/2020-Leg.II]

DIWAKAR SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number S.O. 859(E), dated the 15th April, 1961 and were last amended *vide* notification number S.O. 3667(E), dated the 19th October, 2020.